जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना।

– अज्ञात

टिड्डी दल का देश में उत्पात

आठ–दस बड़े राज्यों में जारी उनका उत्पात अभी उस हद तक राष्ट्रीय अजेंडे पर नहीं आ पाया है, जितना इसे आना चाहिए था। पिछले डेढ़ महीने से पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के रास्ते टिड्डी दल देश में घुसते चले आ रहे हैं।

संजय भट्ट।

दो दिन पहले टिड्डी दलों के गुड़गांव पहुंचने और दिल्ली के कुछ हिस्सों समेत एनसीआर के कई इलाकों में छा जाने से टिड्डियां अचानक खबरों में आ गईं, लेकिन हकीकत यही है कि देश के आठ–दस बड़े राज्यों में जारी उनका उत्पात अभी उस हद तक राष्ट्रीय अजेंडे पर नहीं आ पाया है, जितना इसे आना चाहिए था। पिछले डेढ़ महीने से पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के रास्ते टिड्डी दल देश में घुसते चले आ रहे हैं।

इससे पहले इन्होंने राजस्थान, गुजरात और पंजाब के किसानों को संकट में डाला था, लेकिन इस बार के धावे में इन्होंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे दूर के राज्यों में भी किसानों का जीना हराम कर रखा है।

कोरोना, लॉकडाउन, और सीमा पर तनाव जैसी चौतरफा चुनौतियों से जूझती केंद्र सरकार के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान टिड्डी दलों से मुकाबले पर केंद्रित करना फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन इससे मिलती–जुलती समस्याएं अभी दुनिया के कई और देशों के सामने भी हैं, जिससे टिड्डी दलों का खतरा बहुत बड़ा हो गया है।

सबसे बुरी स्थिति पूर्वी अफ्रीका के देशों में है, जहां पिछले 70 सालों के सबसे भीषण टिड्डी हमलों ने केन्या, युगांडा, सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, इरीट्रिया और जिबूती जैसे देशों में अकाल की नौबत ला दी है। यहां 50 लाख से भी ज्यादा लोगों के सामने भुखमरी का खतरा पैदा हो गया है। भारत में इसको पिछले 25 वर्षों का सबसे घातक हमला बताया जा रहा है लेकिन कोई नहीं जानता कि अगर जल्द ही इनका सफाया नहीं किया गया तो इनसे होने वाला नुकसान कहां जाकर थमेगा। ध्यान रहे कि जुलाई–अगस्त के महीने ही भारत में टिड्डियों के हमले के लिए जाने जाते रहे हैं। ऐसे में आशंका यह है कि आने वाले दिनों में टिड्डी दल अफ्रीका से निकलकर भारत का रुख करेंगे।

गैर रेगिस्तानी इलाकों में टिड्डियों के अंडे देने का समय भी यही होता है। बारिश से गीली और ढीली हुई मिट्टी इन्हें अंडे देने का सुनहरा मौका मुहैया कराती है। लेकिन टिड्डियों की चुनौती सिर्फ भारत के लिए नहीं है। संयुक्त राष्ट्र को भी इनके सफाये की मुहिम को अपनी प्राथमिकता में शामिल करना होगा। यूएन फूड ऐंड ऐग्रिकल्चर ऑर्गनाइजेशन आगाह कर चुका है कि समय रहते काबू नहीं पाया गया तो टिड्डी दलों की यह समस्या कई साल तक दुनिया का पीछा करती रह सकती है। उस स्थिति में सबसे अच्छी सूरत में भी 30 से 40 फीसदी खाद्यान्न का नुकसान अवश्यंभावी है।

सूरत उतनी अच्छी नहीं रही तो यह 50 से 70 फीसदी तक भी जा सकता है। जब कोरोना के चलते दुनिया खाद्य वस्तुओं की कमी और सप्लाई चेन टूटने के कारण पहले से ही खाद्य संकट के मुहाने पर खड़ी है, तब टिड्डियों की समस्या के विकराल रूप धरने की गुंजाइश भला कैसे छोड़ी जा सकती है।

मैं मुक्त कब होऊँगा

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

जब तुममें यह मैं और मेरा – यह अज्ञान है , तुम और तुम्हारा यह ज्ञान है। जो ठीक ठीक भक्त होता है, वह कहता है, हे प्रभो! तुम्हीं कर्ता हो तुम्ही सब कुछ कर रहे हो। मैं तो केवल तुम्हारे हाथों का यन्त्र मात्र हूँ , तुम मुझसे जैसा करवाते हो वैसा ही मैं करता हूँ। यह धन , ऐश्वर्य , यह जग तुम्हारी ही महिमा। यह घर , यह परिवार सब कुछ तुम्हारा है , मेरा कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारा दास हूँ। जैसा तुम्हारा हुक्म होगा , वैसी ही सेवा करने भर का मुझे अधिकार है। आधुनिक जापानी विचारक बौद्ध शिक्षा के निहितार्थ का शोध कर रहे हैं और उसे विकसित कर रहे हैं। उन्होंने प्रतीत्य समुत्पद की अवधारणा को चुना हैदृ आश्रित उत्पत्ति या आपसी अन्योन्याश्रयदृ रचना में सब कुछ और पूरी तरह से अलग अर्थ के साथ यह संचारित होता है।

संपादकीय

थोड़ी संवेदनशीलता

आखिर वजह क्या है कि पश्चिमी घाट के सिकुड़ने के कारणों, उसके परिणामों और उसे बचाने के उपायों की पूरी जानकारी होते हुए भी जमीन पर कुछ नहीं हो पाता? गाडगिल पैनल की रिपोर्ट पड़ी–पड़ी धूल खाती रह जाती है? इन सवालों से तो टकराना ही होगा, यह भी समझना होगा कि बाढ़ और सूखा अलग–अलग आपदाएं नहीं हैं। ये एक–दूसरे से जुड़ी हैं। मॉनसून के दौरान बाढ़ की विनाशलीला देखने और बाकी साल जल संकट से जूझते रहने के बाद भी यह बात हमारी समझ से परे रह जाती है कि बाढ़ के रूप में जितनी बड़ी मात्रा में वर्षा जल व्यर्थ बह जाता है, अगर उसके आधे जल का भी संरक्षण कर लिया जाए तो अगले दो दशकों तक देश में जल संकट की कमी नहीं रहेगी और खेतों में सिंचाई के लिए भी पर्याप्त जल होगा। अलबत्ता इधर उत्तर प्रदेश और बिहार में इस दिशा में कुछ कार्य शुरू किया गया है। वहां मनरेगा के तहत हजारों तालाबों की गहराई बढ़ाने से लेकर उनके किनारों का पक्कीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। इससे बारिश के पानी की कुछ मात्रा तालाबों में जरूर सहेजी जा सकेगी।

जल प्रबंधन की कारगर योजनाएं, तटबंधों की समय से मरम्मत जैसे कदम इनके लिए जरूरी तो हैं पर काफी नहीं हैं। इन सबके साथ ही जंगल, पहाड़, नदी, झील समेत पूरी पारिस्थितिकी के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता की जरूरत है, सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, सरकारी नीतियों के स्तर पर भी। सरकार की प्राथमिकताओं और विकास के मॉडल का सवाल यहीं पहुंच कर प्रासंगिक हो जाता है।

निया भर में बाढ़ के कारण होने वाली मौतों का पांचवां हिस्सा भारत में होता है और हर साल इससे देश को कम से कम एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है।

अध्ययन करके रख लिया

योगेश कुमार गोयल।।

मॉनसून की शुरुआत के साथ ही असम और बिहार में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। असम में अब तक दो दर्जन जिलों के पांच लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और 50 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। बिहार में भी कोसी, महानंदा, कमला बलान और बागमती नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दायरा बढ़ रहा है। दुनिया भर में बाढ़ के कारण होने वाली मौतों का पांचवां हिस्सा भारत में होता है और हर साल इससे देश को कम से कम एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है। बाढ़ से जान–माल की क्षति तो होती ही है, संबंधित राज्य विकास की दौड़ में भी वर्षों पीछे चला जाता है।

करीब दस वर्ष पूर्व चिंता जताई गई थी कि भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर वर्षा के बादलों को मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पश्चिमी घाट मानवीय हस्तक्षेप के चलते सिकुड़ रहा है। उसके बाद मामले के सभी पहलुओं का अध्ययन करके रिपोर्ट देने के लिए केंद्र द्वारा 'गाडगिल पैनल' का गठन किया गया था। पैनल ने समय से अपनी रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन वह ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा सन 1900 के बाद साल

दर साल हुई वर्षा के आंकड़ों के आधार पर 2014 में किए गए अध्ययन में बताया गया था कि ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते मानसूनी बारिश की तीव्रता बढ़ती जा रही है और विनाशकारी बाढ़ की घटनाएं आगे और बढ़ेंगी।

आजादी के कुछ वर्षों बाद 'राष्ट्रीय बाढ़ आयोग' की स्थापना हुई थी, जिसके जरिये राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 150 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई हजार किलोमीटर लंबे तटबंध और बड़े पैमाने पर नालियां व नाले बनाए गए। साथ ही निचले क्षेत्रों में बसे कई गांवों को ऊंची जगहों पर बसाया गया। पिछले पचास सालों में बाढ़ पर सरकारों द्वारा 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राशि खर्च की जा चुकी है। इसके बावजूद यदि हालात साल–दर–साल बदतर हो रहे हैं तो कमी आखिर कहां है?

उत्तरी बिहार को वहां की उफनती नदियों के कहर से बचने के लिए कई मजबूत तटबंध बनाए गए थे, जो दशकों तक काम आते रहे लेकिन अब इनमें से कई तटबंध अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि थोड़ी सी बारिश में ही उनमें जगह–जगह दरारें आ जाती हैं। ऐसी ही बड़ी–बड़ी दरारों के कारण पिछले साल बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से भारी तबाही हुई थी। वैसे भी देश के विभिन्न हिस्सों में बांधों के टूटने या उनमें आने वाली दरारों के चलते प्रतिवर्ष बाढ़ का विकराल रूप सामने आता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि बाढ़ को प्राकृतिक आपदा का नाम देकर पल्ला झाड़ने के बजाय बांधों की मजबूती और मरम्मत के लिए समुचित कदम क्यों नहीं उठाये जाते? भारी वर्षा से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन क्यों नहीं मानसून से पहले ही मुस्तैद होता?

अनियोजित और अनियंत्रित विकास के चलते हमने पानी की निकासी के अधिकांश रास्ते बंद कर दिए हैं। ऐसे में बारिश कम हो या ज्यादा, पानी आखिर जाएगा कहां? दूसरी समस्या यह है कि प्रकृति में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के चलते समुद्रों का तल लगातार ऊंचा उठ रहा है। इससे समुद्रों में नदियों का पानी समाने की गति कम हो गई है। यह भी अक्सर बाढ़ का बड़ा कारण बनता है।

अष्टयोग- 5101

5	3	2		1	6	
	27		24		33	
	5	3		7	1	
1	30	6	37	3	34	5
7	1				2	4
	38		40		26	
	7	4		5	2	1

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5100 का हल

2	3	5	4	1	6	7
1	30	6	34	2	31	3
5	1	7	3	6	2	4
6	30	1	33	3	34	5
3	5	2	4	7	1	6
7	35	4	35	4	28	2
4	7	3	6	5	2	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

जल संकट से निपटने में मिले मदद

मोहन। बाढ़ से नुकसान कम हो, इसके लिए हमें नदियों में गाद का भराव कम करना होगा, साथ ही निचले स्थानों को और गहरा कर उनमें बारिश तथा बाढ़ के पानी को एकत्र करने की ओर ध्यान देना होगा, जिससे बाढ़ के खतरे से निपटने के साथ–साथ गर्मियों में जल संकट से निपटने में भी मदद मिले। ऐसी पहल देश के हर राज्य में की जानी चाहिए। मगर इस तथ्य को भी रेखांकित करने की जरूरत है कि तकरीबन सभी राज्यों में तालाब जिस तेजी से विलुप्त होते गए हैं, उसके पीछे केवल प्राइवेट बिल्डरों और अन्य माफिया की गैरकानूनी अतिक्रमणकारी गतिविधियों की ही भूमिका नहीं है। सरकारी योजनाओं के तहत पूर्ण कानूनी स्वरूप में चलाए गए कई प्रॉजेक्ट भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। सरकार की प्राथमिकताओं और विकास के मॉडल का सवाल यहीं पहुंच कर प्रासंगिक हो जाता है।